EDITORIAL

Where the Government is heading us

The celebrations of completion of three years of the present Government headed by Shri Narendra Modi is reverberating everywhere at the cost of public money. The public sectors and financially struggling companies like BSNL are not spared in the exercise of spending money to these kind of celebration meetings. When look deep into the affairs of the present government, the picture we get is bleak.

The proud railway system of India is being dismantled. The separate railway budget was merged with general budget with ulterior motives. Entire designing, construction, maintenance activities of the grand old Indian Railways is either outsourced or privatized. Even the welfare schemes like Railway schools, Hospital- dispensary systems are at stake. Famous engine factories are given to MNCs. Thousands of Railway stations are being given to contractors in the name of SFM- station Facilitation Managers.

Coal India workers are in their struggle path against closures of mines, dismantling social security measures and safety of mine workers. Fortunately to assuage their feelings, cabinet secretary has agreed to take coal India as one unit for consideration of wage revision.

Decision has been taken to allow 100 % FDI in defence, telecom, aviation, power, mining, petroleum sectors. The Planning Commision was replaced by NITI Aayog to execute the will of the Government without any discussion either in the parliament or in public space. Medias are tamed and most of them become the voices of Government. Reliance Mutual Fund has become the main consultancy for selling the high profit making public sectors like ONGC, Oil India, IOC, BHEL etc and this one thro the new route namely ETF- Exchange Traded Fund.

In the insurance sector 25 % shares were assured to both Indian and foreign private companies. On the other hand corporate companies have become the pets of the ruling class. Concessions are given in taxes and tax evasion was also allowed to the extent of 6 lakh crore. Public sector banks are asked to be friendly with the corporates on issuing loans in thousands of crore and no action is being taken if the loans unpaid. Banks are suffering because of these 7 lakh crore Non Performing Assets. Even Pharmaceutical companies are not spared and being diverted to the road of privatization. By dismantling public sector, the government is playing with bad economics and compromising security and self reliance of our great country.

Farmers of various states have been on serious and continuous struggles . Some of them attained martyrdom on account of gun shots of police forces. Drought Relief, Fair prices for the yield, crop loan are some of their demands. If the Government is ready to spare one lakh crore to the agriculture crisis, the distress of our farmers will be reduced. Unfortunately the Government is not lending its ears even to hear them. The much publicized MNREGA- the rural employment scheme is also under attack. Even the insufficient 100 days work is not guaranteed in many districts. Wage is also not paid then and there.

The unfortunate pressure on Aadhar is threatening the rule sticking crores of people. The Government is not listening to the court authorities and the democratic opinions of various experts.

The Education institutions are being targeted on ideological grounds and attacks on students and research scholars are becoming news of every day. The Government allocation to this sector is reduced and foreign institutions are allowed to loot our students by commercializing the sector. The fees levied are now three times higher in reputed institutions.

Gender budget is also cut. Funds for Announced schemes are also not allotted. The safety of our sisters and protecting them from violence have become tough tasks. The Budget for SC/ST welfare is not properly utilised. The worst cruel job of manual scavenging is still a challenge to the modern nation like India. The workers involved were not given alternate jobs and the rehabilitation fund is also reduced. The jobs on reservation are shrinking. Atrocities on Dalits are increasing. Even the food habits are questioned.

Central Government employees are made to wait to get their new allowances for the last 18 months. The Government is yet to take a decision. Hundreds of Public sector employees

including BSNL, MTNL are excluded from the recommendations of third PRC in the name of Affordability and Profitability. There will be serious unrest in all sectors .The telecom sector will face the crisis if 2 lakh employees and Officers are not given their due revision even after 10 years.

We can enlist more and more. Let us understand the present Government and its governance. Let us be part of all the movements that are echoing the voices of our people and their sufferings. Let us rally ourselves to face the attacks coming on telecom and to get the wage revision at any cost.

संपादकीय

सरकार हमें किस ओर ले जा रही है

श्री नरेन्द्र मोदी की नेतृत्त वाली वर्तमान सरकार के तीन साल पूरा होने का जश्न सार्वजनिक धन खर्च कर सर्वत्र मनाया जा रहा है। आर्थिक संकट झेल रहे, बी.एस.एन.एल. जैसे कम्पनियों को भी इस उत्सवों पर धन खर्च करने को बाध्य किया गया। वर्तमान सरकार के इन मामलों में गहराई से देखने पर उदासीन तस्वीर परिलक्षित होती है।

भारत की गौरव, रेलवे जैसे संस्थानों को ध्वस्त किया जा रहा है। कुटिल इरादों के साथ रेलवे बजट को सामान्य बजट के साथ विलय कर दिया गया। भारतीय रेलवे के पुरानी जरिया को ध्वस्त करते हुए समस्त डिजाइनिंग, निर्माण, रखरखाव, की गतिविधियां या तो "ऑउटसोर्स" की जा रही है या तो निजीकरण कर दी गई है। प्रसिद्ध इंजिन कारखानों को बहु राष्ट्रीय कंपनियों को सौपी जा रही है। रेलवे स्टेशन ठेकेदारों को सौंप दिये गये हैं।

खाद्वानों के बंद करने, कोयला मजदूरों को मिलने वाली समाजिक सुरक्षा एवं संरक्षा को ध्वस्त करने के खिलाफ कोल– इन्डिया के मजदूर–कामगार संघर्ष कर रहे हैं। उनके आक्रोशित भावनाओं के मद्देजनर भारत सरकार के मंत्री मंडलीय सचिव ने समस्त कोल–इंडिया को एक यूनिट मानकर वेतन पुनरीक्षण करने की बात मान ली है।

रक्षा उत्पादन, दूरसंचार, विमानन, बिजली, खनन तथा पेट्रोलियम क्षेत्र में शत–प्रतिशत एफ.डी.आई. देने की निर्णय लिये जा चुके हैं तथा इसको पूरा करने के लिये ही बिना संसद में चर्चा किए "योजना आयोग" का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया है। अधिकांश मिडिया सरकार की आवाज बन गये हैं। उच्च लाभ प्रदत कंपनियां यथा, ओ.एन.जी.सी., ऑयल–इंडिया, आई.ओ.सी. बी.एच.ई.एल आदि को बेच देने हेतु "रिलायंस म्युचुअल फंड को मुख्य परामर्शदाता नियुक्ति किया गया है तो बिक्री हेतु इंक्सचेंज ट्रेड फन्ड (ई.टी.एफ) नाम से एक नयी रास्ता बनाई गई है।

बीमा क्षेत्र में भारतीय एवं विदेशी निजी कंपनियों को पच्चीस प्रतिशत हिस्सा देने का आश्वासन दिया गया। कारपोरेट कम्पनियां शासक वर्ग की चहेता बन गई हैं इन्हें कर में छूट देने के अलावा छः लाख रूपये तक टैक्स में की गई हेरा–फेरी को माफ कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को कार्पोरेट घरानों से मित्रवत रिस्ता रखने की हिदायत है तथा उन्हें असानी से हजारों करोड़ों रूपये ऋण मुहैय्या कराना है और जब ये ऋण बैंकों को वापस नहीं होते तो सरकार कोई कार्यवाई नहीं करती है। भारतीय बैंक सात लाख करोड़ की "नॉन पारफार्मिंग एसेट्स के चलते पीड़ा झेल रहे हैं। फार्मास्यूटिकल कम्पनियों को भी वंचित नहीं रखा गया है और उन्हें भी निजीकरण के मार्ग पर ढकेला जा रहा है।

सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म करके सरकार गलत वित्तीय मार्ग का अनुशरण कर रही है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा एंव संप्रभुता के साथ समझौता कर रही है।

कई राज्यों में किसान निरंतर संघर्षरत हैं। इनमें से कुछेक पुलिस की गोली का शिकार होकर काल–कलवित हो चुके हैं। सूखे से राहत, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य, फसल ऋण आदि उनकी प्रमुख मांग हैं। सरकार अगर एक लाख करोड़ रूपये कृषक हित पर खर्च करे तो किसानों की पीड़ा कम हो सकती है। दुर्भाग्यवश सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। बहुप्रचलित "मनरेगा" जो ग्रामीण रोजगार योजना है, आक्रमण का शिकार बन चुकी है।

देश के कई जिलों सरकार द्वारा दी गई सौ दिनों की रोजगार गारंटी पर कोई अमल नहीं है। मजदूरों की उनकी मजदूरी कार्य स्थल पर नहीं मिल रही है।

"आधार कार्ड" के मुद्दे पर सरकार' अदालत एवं विशेषज्ञों की सलाह को अनसुनी कर रही है। आधार के अभाव से करोड़ों नागरिक दुर्भाग्यपूर्ण दवाब झेल रहें हैं। शैक्षिक संस्थानों को निशाना बनाते हुए आयडियोलाजी के नाम पर शिक्षकों, छात्रों एवं शोधकर्त्ताओं पर हमले की खबर आम हो गई है। शिक्षा क्षेत्र में सरकार की लागत कम की गई है तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की छूट दी जा रही है। सभी स्तरीय शैक्षिक प्रतिष्ठानों की शुल्क तीन गुणा तक बढ़ा दिये गए हैं।

महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं के फंड में कटौती कर दी गई है। इनके लिए घोषित स्कीम के वास्ते भी रकम नहीं जारी किये गये हैं जिससे बहनों की सुरक्षा एवं हिंसाक वरदातों से बचाना एक हवा की बात बन गई है। एस.सी./एस.टी. कल्याण के लिए भी आवंटित रकम का सदुपयोग नहीं हो रहा है और भारत जैसे देश में आज भी सिर पर मैला ढोने की प्रथा बदस्तर जारी है। इस पेशे में कार्यरत मजदूरों की वैकल्पिक कार्य एवं पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो रही है। आरक्षण की नौकरियां सिकुड़ रही है और दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। जवलंत समस्याओं को नजर अंदाज करते हुए नागरिकों की भोजन की आदतों को मुख्य रूप से उछाला जा रहा है।

केन्द्र सरकार के कर्मचारी गत अठारह माह से नये भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। अर्थिक सक्षमता और लाभ प्रदता के नाम पर बीएसएनएल/एम.टी.एन.एल एवं अन्य कम्पनियों को तृतीय वेतन पुनरीक्षण से बाहर रखा गया है। सभी लोक–क्षेत्रों में जन–अशांति बनी हुई है। अगर दस साल के बाद भी बीएसएनएल के दो लाख कर्मचारी अधिकारी वेतन पुनरीक्षण के लाभ से वंचित रहेगे तो दूरसंचार क्षेत्र को भारी अशांति का सामना करना पड़ेगा। हम विशंगतियों की लम्बी सूची बना सकते हैं।

आइये हम वर्तमान सरकार एवं इसके शासकीय चरित्र को समझने का प्रयास करें। आइये हम उन आंदोलनों का हिस्सा बने जो आहत जन समुदाय की आवाज को बुलंदियों तक पहुंचा सके। आइये हम दूरसंचार क्षेत्र खासकर हमारे बीएसएनएल पर होने वाले प्रहार की चुनौतियों को समझें और एकताबद्ध होकर किसी भी हालत में तृतीय वेतन पुनरीक्षण की गारंटी करें।